नए राष्ट्रपति की नीतियों पर हैं निगाहें

मिशेल ऑस्टीन

ओबामा के प्रचार अभियान में यह बात बार-बार दोहराई गई कि वह विदेश नीति में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएंगे जिससे विश्व में अमेरिका की छवि बहाल हो सकेगी।

अमेरिका में 20 जनवरी 2009 को बाराक ओबामा का राष्ट्रपति पद की शपथ लेना विदेश नीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि नीतियों में बदलाव तुरंत नहीं हो जाएंगे।

चार नवंबर को सेंटर फ़ॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के स्टीफन फ़्लैनागेन ने विदेश मंत्रालय के फॉरेन प्रेस सेंटर में पत्रकारों को बताया कि ओबामा प्रशासन के लिए विदेश नीति में ''वास्तविक प्रगति की संभावना मौजूद है।'' फ़्लैनागेन ने कहा कि ''अपेक्षाएं काफी अधिक हैं'' लेकिन ''नए राष्ट्रपति पर तुरंत आ पड़ने वाले वैश्विक वित्तीय संकट की स्थिति, विदेशों में दो बड़े सैन्य अभियानों और घरेलू मोर्चे पर अन्य कई प्राथमिकताओं के भार को देखते हुए बदलाव आने में कुछ समय लग सकता है।''

चुनाव अभियान के दौरान ओबामा और उनके कर्मचारी अमेरिका के सहयोगियों के साथ कार्य करने और सम्बन्धों को मज़बूत बनाने की उनकी इच्छा पर बल देते रहे हैं। उनके अभियान ने बार-बार स्पष्ट किया कि ओबामा विदेश नीति का एक ऐसा बहुपक्षीय तरीका लागू करेंगे जो विश्व में अमेरिका की छवि को पुनर्स्थापित करेगा।

फ़्लैनागेन ने कहा, ''अंतरराष्ट्रीय समुदाय से एक नए तरीके से व्यवहार रखा जाएगा'' और ''बहुपक्षीयता के प्रति अधिक प्रतिबद्धता'' दिखेगी। काफी लोग इस तरीके का स्वागत करेंगे। स्टीफन फ़्लैनागेन ने कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सर्वेक्षणों को उद्धरित किया जिनसे पता चलता है कि ''इस समय अमेरिका में ज़बर्दस्त ढंग से यह भावना दिखती है कि हमारी विदेश नीति पूरी तरह सही दिशा में नहीं चल रही है।''

संसार की निगाहें इस बात पर लगी रहेंगी कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति किस तरह सहयोगियों के साथ काम करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संवाद रचेंगे और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करेंगे। दूसरे देशों की धरती पर चल रहे दो युद्धों को देखते हुए अधिसंख्य अमेरिकियों की अपेक्षा है कि इराक और अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति ओबामा की विदेश नीति का सर्वोच्च सरोकार बने। साथ ही, वैश्विक पैमाने पर महसूस किए जा रहे वित्तीय संकट को भी प्राथमिकता मिले।

फ़्लैनागेन ने कहा कि पद ग्रहण करने से भी

पाब्लो मार्टिनेज मोनसिवैस © ए.पी. - डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाराक ओबामा और उनकी विदेश नीति टीम के सदस्य (बाएं से) विदेश मंत्री-मनोनीत हिलेरी क्लिंटन, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत- मनोनीत सूसन राइस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकर- मनोनीत जेम्स जोन्स।

पहले ओबामा इराक युद्ध को प्रबंधित करने संबंधी नए प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और ''इराकी जनता के प्रति और उत्तरदायित्व को धीरे-धीरे कम करने'' की अपेक्षा रखेंगे। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हिंसक चरमपंथिता और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष की एक अधिक वैश्विक पैमाने पर भी पड़ताल करेंगे और वह इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए एक अधिक बहुपक्षीय तरीके की ज़रूरत है।

फ़्लैनागेन के अनुसार जलवायु परिवर्तन में यूरोपीय समुदाय की विशेष रुचि है और इस क्षेत्र में भी ओबामा बहुपक्षीय तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अगले राष्ट्रपति यूरोपीय सहयोगियों के साथ साझेदारियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे और रूस के साथ साझे हित के क्षेत्रों में काम कर पाने के उपाय भी ढूंढेंगे।

ओबामा प्रशासन को कई एशियाई देशों से मज़बूत संबंध विरासत में मिलेंगे और उनके विशेष रूप से चीन और भारत पर ध्यान देने की संभावना है जो दो ऐसी बड़ी शक्तियां हैं जो ''अंतरराष्ट्रीय आर्थिक तंत्र में बड़ी भूमिका निभाएंगीं।''

ओबामा प्रशासन के ''अफ्रीका के बढ़ते महत्व'' को स्वीकार करने की भी संभावना है और फ़्लैनागेन को आशा है कि वह इस महाद्वीप में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। फ़्लैनागेन ने कहा: ''ओबामा को कुछ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों के प्रति अधिक आलोचनात्मक रुख रखने वाला माना जाता है लेकिन मैं नहीं मानता कि मुक्त व्यापार विरोधी भंगिमा जैसा कुछ है, हां मैं यह ज़रूर मानता हूं कि यह इन समझौतों की प्रक्रिया पर अधिक गौर करने की इच्छा है।''

ओबामा प्रशासन को एशिया में कई देशों के साथ मज़बूत संबंध विरासत में मिल रहे हैं। फ़्लैनागेन के अनुसार उम्मीद है कि ओबामा क्षेत्र की दो प्रमुख ताकतों चीन और भारत पर विशेष ध्यान देंगे।

किसी भी अन्य राष्ट्रपति की तरह किसी मसले पर ओबामा को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना होगा। फ़्लैनागेन कहते हैं, ''लगभग अवश्यंभावी है कि कोई अंतरराष्ट्रीय किस्म की घटना होगी- आतंकी हमला या वित्तीय संकट से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण समस्या। यह कोई ऐसी घटना होगी जो अगले राष्ट्रपति की परीक्षा सिद्ध होगी।''

कई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही बड़े अंतरराष्ट्रीय संकटों का सामना कर चुके हैं। अपने राष्ट्रपतित्व के नवें महीने में ही राष्ट्रपति बुश ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद देश का नेतृत्व किया।

यही कारण है कि निर्वाचित राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने से पहले अपनी विदेश नीति टीमों का गठन शुरू कर देते हैं। पद ग्रहण करने से कई सप्ताह पहले ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण पदों के लिए टीम तय कर लेते हैं जो विदेश नीति लक्ष्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

***मिशेल ऑस्टीन** America.gov से संबद्ध हैं।*